# एक वैध लक्ष्य के लिए अनुचित प्रयास

लेखक - रामकिशन एस. राजन (प्रोफेसर, सिंगापुर के ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी) शशिद्रन गोपालन (सिंगापुर के नानयांग बिजनेस स्कूल में सीनियर रिसर्च फेलो)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

19 जुलाई, 2019

## "आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें निजी निवेश में वृद्धि के लिए कही गयी बात सही है, लेकिन यह पूर्वी एशियाई मॉडल से अपने आप को अलग कर रही है।"

हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली कई चुनौतियों की या तो अनदेखी करता है या इस इन चुनौतियों का बोध नहीं है। इन चुनौतियों में गंभीर कृषि संकट; घाटे में चल रही और कर्ज में डूबी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां; और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को परेशान करने वाले मुद्दे शामिल हैं।

हालांकि, सर्वेक्षण मनोविज्ञान से अर्थशास्त्र में अंतर्दृष्टि को शामिल करने के महत्व को उजागर करने में गलत नहीं है, लेकिन यह अजीब है कि इसे इतनी देर से किया गया। यू.के., ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे कई अन्य देशों द्वारा भी लंबे समय से नीति डिजाइन और कार्यान्वयन क्षेत्रों में इस तरह के बिंदुओं को लागू किया जा रहा है और इस मुद्दे पर पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी चर्चा हुई है। एक मुद्दे को सर्वेक्षण ने सही रूप से रेखांकित किया है कि भारत को निजी निवेश को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, यदि इसे 2024-25 तक जादुई 5-ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करना है। हालांकि, यहाँ जो अजीब है, वह यह है कि इस पर जोर देने के लिए, दस्तावेज भारत और पूर्वी एशियाई देशों के बीच सदियों पुरानी तुलना को आमंत्रित करता है।

### कैसे एनआईई समृद्ध हुआ?

यहाँ, एक सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या पूर्वी एशियाई मॉडल भारत की उलझी हुई निवेश दरों को पुनर्जीवित करने में मदद् कर सकता है? कुछ महत्वपूर्ण अनुस्मारक रेखांकित करने योग्य हैं।

पूर्व एशियाई मॉडल काफी हद तक सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और ताइवान एवं जापान के नव औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं (एनआईई) द्वारा संचालित एक कहानी थी।

विशेष रूप से, 1960 के दशक से 1990 के दशक तक (एशियाई वित्तीय संकट से पहले) विभिन्न एनआईई में मुख्य लक्ष्य सकल बचत दरों को बढ़ाना था। जबकि घरेलू बचत में वृद्धि आंशिक रूप से सकारात्मक जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण हुई, कई अन्य कारकों, जिनमें व्यापक आर्थिक स्थिरता, कम मुद्रास्फीति, सामाजिक सुरक्षा की कमी, लाभ उठाने में असमर्थता (अत्यधिक विनियमित बैंकिंग प्रणाली के कारण) और बाध्यकारी बचत (पूरी तरह से वित्त पोषित भविष्य निधि) शामिल हैं, ने भी एक भूमिका निभाई है। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को बजट की कमी के साथ काम करना पड़ता था।

एक अन्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि निजी बचत को वास्तव में औपचारिक वित्तीय प्रणाली में मध्यवर्ती किया जाना था, जिसमें यह विफल रहा क्योंकि पूंजी की लागत अधिक रही और निवेश के लिए पूंजी की उपलब्धता कम रही। इसे प्राप्त करने के लिए, एक सुरक्षित और सुरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली (आमतौर पर डाक बचत नेटवर्क के रूप में) की स्थापना को महत्व दिया गया था, जहाँ केंद्रीय बैंक द्वारा जमा की गारंटी दी गई और ब्याज आय पर हल्के ढंग से कर अधिरोपित किया गया था। राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को बेहतर ढंग से विनियमित किया गया था क्योंकि वित्तीय स्थिरता समग्र व्यापक आर्थिक स्थिरता की आधारशिला थी।

वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया गया था। हालांकि ध्यान केवल उनके खातों को खोलने के बजाय जमा खातों के वास्तविक उपयोग पर था। जबकि निर्माण क्षेत्र को एक विकास इंजन के रूप में देखा गया था और निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए खुला था, बैंकिंग क्षेत्र,

हांगकांग के अलावा सभी अर्थव्यवस्थाओं में, बेहतर विनियमित और विदेशी बैंकों के लिए बंद था। यहाँ तक कि सिंगापुर ने शुरू में एक दोहरी बैंकिंग संरचना को अपनाया, जिसने घरेलू अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण अल्पकालिक बैंक प्रवाह से आश्रय दिया। 1990 के दशक के अंत तक पूरी तरह से लाइसेंस प्राप्त विदेशी बैंकों को अनुमति देने के लिए इसने एक अंशांकित नीति का सहारा लिया।

## तंग वित्तीय निरीक्षण

यह सामान्य परिस्थितियों में, औपचारिक वित्तीय प्रणाली से विघटन का कारण होगा, जिसके परिणामस्वरूप वित्तपोषण की मात्रा में कमी और शैडो बैंकिंग प्रणाली का निर्माण होगा। हालांकि, इन अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने कड़ी निगरानी बनाए रखी और चयनात्मक पूंजी नियंत्रण ने यह सुनिश्चित किया कि कम उपज वाली बचत ने अपने मूल देशों को नहीं छोड़ा, जबकि सीमित वित्तीय विकास ने बचत के विकल्प की तलाश कर रहे लोगों की संभावना को कम कर दिया।

इनके साथ ही, सरकारों ने घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए परिष्कृत औद्योगिक नीतियां अपनाई, जिनमें से अधिकांश निर्यात-नेतृत्व वाली थीं (हालांकि आवश्यक रूप से मुक्त-बाजार आधारित नहीं थी)। सरकारें समझती थीं कि एक ऊर्ध्वाधर औद्योगिक नीति एक क्षैतिज औद्योगिक नीति (श्रम और भूमि सुधारों से निपटने, बुनियादी साक्षरता लाने और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने) के बिना काम नहीं करेगी।

## विषम नीतियां, सुधार

इस प्रकार, पूर्व एशियाई देशों में निवेश और निर्यात की अधिकता विषमतावादी नीतियों और सुधारों के कारण थी, जिसे सावधानीपूर्वक जाँचा गया था, अच्छी तरह से अनुक्रमित और कार्यान्वित किया गया था। इन उपायों ने राष्ट्रों को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश से लाभान्वित होने और रिकॉर्ड समय में खुद को विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बदलने की अनुमति दी।

इसके विपरीत, राजनीतिक और अन्य मजबूरियों के कारण, 1991 के बाद से भारत के सुधारों में बहुत जल्दबाजी हुई है और विकृत परिणामों के साथ एक 'स्टॉप-एंड-गो' प्रकृति बनी हुई है।

उत्तराधिकारी सरकारों के पास न तो उपकरण-सेट और नीति अपनी-अपनी जगह पर थे और न ही पूर्वी एशियाई देशों की तरह औद्योगिक परिवर्तन को चलाने के लिए अंतःस्थापित प्रणाली की आवश्यकता थी।

GS World
... to Excellence


## GS World टीम...

### आर्थिक समीक्षा 2018-19

- हाल ही में केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 पेश की।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी किया गया।
- स्वच्छ भारत से सुन्दर भारत किया गया।
- एलपीजी सब्सिडी के लिए 'गिव इट अप' से 'थिंक अबाउट द सब्सिडी' किया गया।
- कर वंचना से कर अनुपालन किया गया।
- छोटी फर्मों का रोजगार में केवल 14 प्रतिशत और उत्पादकता में आठ प्रतिशत योगदान है।
- सौ से अधिक कर्मचारियों वाली बड़ी फर्मों का संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी 15 प्रतिशत होने के बावजूद रोजगार में 75 प्रतिशत और उत्पादकता में 90 प्रतिशत योगदान है।

**मुख्य बिंदु**

- 2024-25 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए आठ प्रतिशत की सतत् वास्तविक जीडीपी विकास दर की जरूरत है।
- **निजी निवेश-** मांग, क्षमता, श्रम उत्पादकता, नई प्रौद्योगिकी, रचनात्मक खंडन और नौकरी सृजन का मुख्य वाहक।

- समीक्षा अर्थव्यवस्था को नैतिक या अनैतिक चक्र के रूप में देखते हुए परम्परागत एंग्लो-सेक्सोन विचारधारा से अलग करते हुए कभी भी समतुल्य न होना।

## अर्थव्यवस्था की स्थिति

- 2018-19 में भारत अब भी तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
- जीडीपी की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में 7.2 प्रतिशत की जगह वर्ष 2018-19 में 6.8 प्रतिशत हुई।
- 2019-20 में विकास दर में तेजी आएगी और इसके 7% रहने का अनुमान है।
- सात प्रतिशत वृद्धि दर का मतलब है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ता रहेगा। वहीं, ग्लोबल ग्रोथ के कम रहने की भी संभावना व्यक्त की गई है।
- 2018-19 में मुद्रास्फीति की दर 3.4 प्रतिशत तक सीमित रही।
- सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में फंसे हुए कर्ज दिसम्बर, 2018 के अंत में घटकर 10.1 प्रतिशत रह गये, जोकि मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत थे।
- चालू खाता घाटा जीडीपी के 2.1 प्रतिशत पर समायोजित करने योग्य है।
- केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में जीडीपी के 3.5 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 3.4 प्रतिशत रह गया।

## राजकोषीय घटनाक्रम

- जीडीपी के 3.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे और 44.5 प्रतिशत (अनंतिम) के ऋण-जीडीपी अनुपात के साथ वित्त वर्ष 2018-19 का समापन।
- जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार, वर्ष 2017-18 के मुकाबले वित्त वर्ष 2018-19 के अनंतिम अनुमान में केन्द्र सरकार के कुल परिव्यय में 0.3 प्रतिशत की कमी।
- राजस्व व्यय में 0.4 प्रतिशत की कमी और पूंजीगत व्यय में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि।

## आर्थिक समृद्धि के लिए लक्ष्य

- डाटा को सार्वजनिक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना।
- कानूनी सुधारों पर जोर देना।
- नीति सामंजस्य सुनिश्चित करना।
- व्यवहारीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए व्यवहार बदलाव को प्रोत्साहित करना।
- अधिक रोजगार सृजन और अधिक लाभकारी बनाने के लिए एमएसएमई को वित्तपोषित करना।
- पूंजी लागत घटाना
- निवेश के लिये व्यापार में लाभ जोखिम को तर्कसंगत बनाना।

## मूल्य और महंगाई दर

- सीपीआईसी पर आधारित महंगाई दर में लगातार 5वें वर्ष गिरावट दर्ज की गई। पिछले 2 वर्षों से यह 4 प्रतिशत से कम रही है।
- उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में भी लगातार 5वें वर्ष गिरावट दर्ज की गई और यह पिछले 2 वर्षों के दौरान 2 प्रतिशत से भी कम रही है।
- 2018-19 के दौरान सीपीआई-सी आधारित महंगाई दर के मुख्य कारक हैं-आवास, ईंधन व अन्य।

## उद्योग और अवसंरचना

- 2018-19 में आठ बुनियादी उद्योगों के कुल सूचकांक में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि।
- विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रिपोर्ट-2019 में भारत दुनिया के 190 देशों में 77वें स्थान पर पहुंचा। पहले की तुलना में 23 स्थान ऊपर उठा।
- बिजली की स्थापित क्षमता 2019 में 3,56,100 मेगावाट रही, जबकि 2018 में यह 3,44,002 मेगावाट थी।

## संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

1. **आर्थिक समीक्षा 2018-19 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. 2018-19 में देश की जी.डी.पी. की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही।
   2. 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आठ प्रतिशत की सतत् वास्तविक जी.डी.पी. विकास दर की जरूरत है।
   3. 2018-19 में मुद्रास्फीति की दर 3.4 प्रतिशत तक सीमित रही।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

   (a) 1 और 2
   (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3
   (d) उपर्युक्त सभी

## Expected Questions (Prelims Exams)

1. **In the context of Economic Survery 2018-19, consider the following statements-**

   1. In 2018-19 the growth rate of G.D.P. was 6.8 percent.
   2. For making the Indian economy 5 trillion dollar economy by 2024-25 the sustainable real G.D.P. growth rate should be 8 percent.
   3. The inflation rate in 2018-19 has been 3.4 percent.

   Which of the above statement are correct?

   (a) 1 and 2 (b) 2 and 3
   (c) 1 and 3 (d) All of above

## Expected Questions (Mains Exams)

**प्रश्न: नव औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं के सन्दर्भ में पूर्वी एशियाई मॉडल की चर्चा कीजिए। ( 250 शब्द )**

**Q. Discuss the East Asian Model in the context of neo industrial . (250 Words)**

**नोट : 18** जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

Commit